

नेगोशिएशन का विकल्प अतिरिक्त विवाद निस्तारण के तौर पर करना चाहिए : जस्टिस अशोक कुमार जैन

नेगोशिएशन का महत्व पुरातन काल से ही रहा है तथा लम्बे समय से ग्रामीण परिवेश में ही छोटे-मोटे झगड़ों का निस्तारण पंचायत के माध्यम से किया जाता रहा है : आर.डी.रस्तोगी

जयपुर। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने द्वितीय आर के रस्तोगी मेमोरियल राष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता 2024 का सफल आयोजन किया। जिसका समापन 29 सितंबर को हुआ। जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार जैन मुख्य अतिथि रहे। समारोह के अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना कटेजा उप कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय ने की तथा सशस्त्र बाल अधिकरण के अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य न्यायाधिपति गोवर्धन बाबुदार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में देशभर की लगभग 35 से अधिक टीमों ने भाग लिया, दो दिवसीय प्रतियोगिता का चार चरणों में आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं ने प्रतिभागियों को कौशल को सराहा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की टीम विजेता रही एवं सिंबोसिस लॉ कॉलेज पुणे में द्वितीय स्थान प्राप्त किया साथ ही सर्वश्रेष्ठ नेगोशिएटर तान्या खनोजा रही, स्पिरिट ऑफ द कम्पीटीशन का पुरस्कार देव माहेश्वरी ने प्राप्त किया।

समापन समारोह में न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने कहा कि नेगोशिएशन का विकल्प विवाद निस्तारण नहीं बल्कि अतिरिक्त विवाद



विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने द्वितीय आर.के.रस्तोगी मेमोरियल राष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता का समापन 29 सितंबर को हुआ। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार जैन मुख्य अतिथि रहे। समारोह के अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना कटेजा उप कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय ने की तथा न्यायिक सदस्य न्यायाधिपति गोवर्धन बाबुदार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

निस्तारण के तौर पर विकसित करना चाहिए जिसमें छोटे मामले न्यायालय में न पहुंचे और न्यायालय पर अधिक भार काम किया जा सके।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर कल्पना कटेजा ने कहा कि नेगोशिएशन केवल वकील को ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति को सीखना

चाहिए तथा सफल नेगोशिएशन का मुख्य आधार धैर्य से आता है तथा उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में कहा कि इस प्रतियोगिता से सभी कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। न्यायाधीश गोवर्धन बाबुदार ने नेगोशिएशन का आधिकारिक उपयोग कर इससे आपसी विवादों की सुलझाने की सलाह दी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी जो कि इस प्रतियोगिता के संरक्षक भी हैं, ने कहा नेगोशिएशन का महत्व पुरातन काल से ही रहा है तथा भारत में लम्बे समय से ग्रामीण परिवेश में ही छोटे-मोटे आपकी झगड़ों का निस्तारण पंचायत के माध्यम से किया जाता रहा है और और मूलतः भारतीयों

का नेगोशिएशन से आपसी समझाइश में इसमें महार विश्वास रहा है।

वीजीयू के सीईओ इंजीनियर अंकार बागड़िया ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यह अत्यंत आवश्यक है कि अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारी टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग सीखें करें जिससे भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के आने से नेगोशिएशन तथा अन्य न्याय वितरण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बन सके वीजीयू के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री संतोष कुमार ने कहा कि नेगोशिएशन को हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि छोटे-मोटे विवाद उत्पन्न ही ना हो और यदि हो भी तो आपसी समझाइश से सुलझाई जा सके। वीजीयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर प्रवीण चौधरी तथा विधि विभाग के डीन प्रोफेसर पी. पी. मित्रा ने सभी को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

विधि विभाग की अध्यक्ष शिल्पा राव रस्तोगी ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शौक्षिक एवं शैक्षणिक साधियों तथा सभी छात्रों को समारोह को सफल बनाने का श्रेय दिया तथा भविष्य में इसी प्रकार की अगली अंतरराष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता आयोजित करने की बात कही।

देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने के लिए भाजपा को मजबूत करना होगा : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में पंचायत राज प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। इसके सदस्य अभियान से अधिक से अधिक जन सामान्य को जोड़कर मजबूत करना होगा। इस अभियान में पंचायत राज प्रकोष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज के अंतिम छोर तक पहुंच का सुगम माध्यम है।

बैठक को संबोधित करते हुए

- 'सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन सामान्य तक लेकर जाएं, फिर सदस्य बनाएं'
- भाजपा पंचायत राज प्रकोष्ठ की सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक

पंचायत राज केविनेट मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रताओं से आग्रह किया कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन सामान्य तक लेकर जाएं और लोगों को लाभ पहुंचा कर पार्टी से जोड़कर राष्ट्र को मजबूत करने

में प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएं। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सदस्य अभियान सहसंयोजक मोती लाल मीणा ने सदस्यता अभियान के लिए पदाधिकारियों को प्रेरित करने एवं निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने का आह्वान

किया। प्रदेश संयोजक रघुवीर सिंह चौधरी ने बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों का संगठनात्मक कार्य विभाजन करते हुए जिला प्रभारियों एवं जिला संयोजकों को सदस्यता लक्ष्य निर्धारित करते हुए पुरा करने का निर्देश दिया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सैनी, प्रकोष्ठ के सहसंयोजक गोविंद प्रभारी, राजेन्द्र मीणा, पायल परसरामपुरिया, उदय सिंह, भावना सैनी, मनिष व्यास, माधव चौधरी सहित सदस्यता समिति सदस्य एवं जिला संयोजक उपस्थित रहे।

राज.वि.वि.में वर्ष 2005 में लागू हुई सामूहिक छात्र दुर्घटना सहायता योजना

जयपुर, (का.सं.)। श्री विशान सिंह शेखावत शोध एवं शिक्षण संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अध्यक्ष डॉ. भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 2005 में सामूहिक छात्र दुर्घटना सहायता योजना लागू हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 2005 में यह योजना स्थाई रूप ले चुकी है। वर्तमान में इस योजना के तहत मृत छात्र के मरने की परिजन को 12 लाख, एवं दुर्घटना में घायल छात्र को चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपय दिए जा रहे हैं, सहायता की यह कुल राशि करोड़ों में पहुंच गई है।

विधि महाविद्यालय से जुड़े एक 22 वर्षीय छात्र को वर्ष 2004 में कॉलेज से घर जाते समय एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। अपनी विधवा माता का यह एकलौता पुत्र था, परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को सामने रखते हुए इस छात्र के परिजनों एवं मित्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष इस छात्र के परिवार, विशेष रूप से इसकी विधवा माता की आर्थिक मदद की गुहार लगाई। विश्वविद्यालय प्रशासन मदद की भावना रखते हुए भी विश्वविद्यालय में इस तरह की सहायता का कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण असहाय हो गया।

गांधी वाटिका को सेलिब्रेट करने का निर्णय

जयपुर। पब्लिक अंग्रेस्ट करणस संस्था ने 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 7 से 8 तक गांधी दर्शन वाटिका को सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में संजय त्यागी एडवोकेट और पूरम चन्द भंडारी एडवोकेट भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम गांधी दर्शन वाटिका सेंट्रल पार्क गेट नंबर 5 पर होगा।

संयोजक डॉ. टी एन शर्मा एडवोकेट और सह-संयोजक कमलेश सक्सेना एडवोकेट ने बताया कि सेंट्रल पार्क सी-स्क्रीम जयपुर में एक लक्ष्मी विलास होटल था और वह अवैध तरीके से करीब 15 हजार गज जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था तथा एक अन्य व्यक्ति ने करीब 5000 गज जमीन पर कब्जा कर मकान बनाकर रह रहा था। जिसके लिए एडवोकेट संजय त्यागी ने जनहित याचिका लगाई।

'आमजन भी भाजपा में शामिल हों'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को भाजपा जयपुर देहात उत्तर जिले की सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। मनोहरपुरा के एक निजी गाईन में बैठक को संबोधित करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार लागतार जनहितैषी कार्य कर रही है। फिर चाहे वो बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हो, या फिर गरीब, दलित और वंचितों के हितों के लिए योजनाओं को शुरू करने की बात हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की भी जिम्मेदारी है कि वे भाजपा परिवार में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करें।

राठौड़ ने कहा कि वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए हर नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है।

- भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर देहात उत्तर जिले की समीक्षा बैठक की

देश-प्रदेश में चल रही गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान में घर-घर जाकर सदस्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना पड़ेगा। भाजपा कार्यकर्ता प्रतिदिन कुछ समय निरंतर सदस्यता अभियान को अवश्य दें। समीक्षा बैठक में राठौड़ ने प्रत्येक कार्यकर्ता को 200 सदस्य बनाने का संकल्प दिलाया।

बैठक में जमवारागढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा, भाजपा प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा सहित

भाजपा पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, भाजपा नेता उपेन यादव, शाहपुरा पालिका अध्यक्ष बंशीधर सैनी, मनोहरपुर पालिका अध्यक्ष प्रताप प्रजापत, मंडल अध्यक्ष रामप्रकाश नाई, जिला महामंत्री बृजेला सोनी, जिला मंत्री ताराचंद चौधरी, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष भावना सहाय बेनीवाल, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामावतार असवाल सहित कई विधायकगण, विधायक प्रत्याशी, जिला पदाधिकारी, पार्टी के निर्वाचित प्रधान, नगर पालिका अध्यक्ष, उप प्रधान, जिले में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, सदस्यता अभियान एवं सेवा पखवाड़ा के जिला संयोजक, सहसंयोजक सभी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, सदस्यता अभियान के सभी मंडल संयोजक, सहसंयोजक उपस्थित रहे।

लंबे समय के बाद खुली हाउसिंग बोर्ड की ई-नीलामी : डॉ.रश्मि शर्मा

'जयपुर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में चार स्लॉट्स में की जाएगी प्रीमियम प्रॉपर्टीज की नीलामी'

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजस्थान आवास मण्डल की ओर से लंबे समय बाद राजस्थान के प्रमुख शहरों में प्रीमियम प्रॉपर्टीज की नीलामी का रज हो रहा है। राजस्थान आवास मण्डल ने जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों में स्थित आवासीय-व्यावसायिक भूखंड एवं निर्मित आवास नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं।

आवास आयुक्त डॉ.रश्मि शर्मा ने कहा कि राजस्थान आवास मंडल एक बार फिर आमजन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राजस्थान के प्रमुख शहरों में प्रीमियम संपत्ति खरीदने का आमजन के पास अब मौका है। आवास मंडल की ओर से जयपुर, भरतपुर, फलीदी, बीकानेर, अलवर, चूरू, सीकर, जोधपुर और भिवाड़ी में प्रीमियम संपत्तियों की ई-नीलामी की जा रही है।

आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि त्योहारी सीजन में आमजन के

लिए प्रीमियम प्रॉपर्टी खरीदने का यह सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि आवास मंडल की ओर से आगे भी विभिन्न आवासीय योजनाओं व नीलामी के प्रयास निरंतर जारी रहेगा। नीलामी में भाग लेने और अधिक जानकारी के लिए आमजन विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके अथवा 27440009, 9460254319, पर संपर्क कर सकते हैं।

डॉ. शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 4 स्लॉट्स में ई-नीलामी होगा। 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 4 अलग-अलग स्लॉट्स में भूखंडों की नीलामी होगी। जिसमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भूखंड और आवासीय निर्माण शामिल हैं।

किस शहर में कितनी प्रीमियम सम्पत्ति?

- जयपुर में 11 बड़े व्यावसायिक भूखंड, 39 छोटे व्यावसायिक भूखंड, 31 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास
- बीकानेर में 46 छोटे व्यावसायिक भूखंड, 7 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास
- भिवाड़ी में 3 बड़े व्यावसायिक भूखंड, 29 छोटे व्यावसायिक भूखंड, 4 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास
- फलीदी में 1 बड़ा व्यावसायिक भूखंड
- अलवर में 3 छोटे व्यावसायिक भूखंड, 7 आवासीय भूखंड और निर्मित आवास
- चूरू में 9 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास
- सीकर में 4 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास
- भरतपुर में 7 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत "मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ" अभियान की शुरुआत आज

नई दिल्ली/जयपुर। देश के किसानों के लिए भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा "मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ" छटा संस्करण शुरू होने जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी और 31 अक्टूबर तक चलेगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत पूरे देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 4.5 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा पॉलिसी के दस्तावेज वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) के तहत सभी बीमित किसानों को उनके पॉलिसी दस्तावेज उन्हें उनके हाथों में सौंप जाएं ताकि उनको उनके फसल बीमा से संबंधित सभी जानकारी पूरी तरह से परदर्शी हो।

किसानों को सशक्त बनाने का मिशन

मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का एक उद्देश्य किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी के प्रति जागरूक करना है ताकि किसानों को बीमा भुगतान संबंधी

समस्याओं का सामना न करना पड़े। ये अभियान किसानों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार किसानों को प्रशिक्षण दे और उनकी शिकायतों से निपटने के लिए फसल बीमा पाठशालाओं के साथ-साथ फसल बीमा के बारे में कम जागरूकता वाले क्षेत्रों में नुकक्रेड नाटक भी आयोजित करेगी। ये समुदाय-स्तरीय सहभागिताएं किसानों को फसल बीमा के लाभों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी

किसानों को मिलेगा आर्थिक कवच

जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित मौसम के बदलाव से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है ऐसे में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का उद्देश्य किसानों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करना है। जलवायु में उतार-चढ़ाव के कारण अप्रत्याशित जोखिमों और नुकसान को कम करने के लिए फसल बीमा महत्वपूर्ण है,

जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान की आय सुरक्षित रहे और अपनी आजीविका बनाए रखें।

इस साल 9 करोड़ से अधिक आवेदन

खरीफ 2023 में 8.65 करोड़ बीमा आवेदन प्राप्त हुए थे और इस वर्ष 9 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए जो कि एक उल्लेखनीय वृद्धि है और यह फसल बीमा योजना में किसानों की बढ़ती रुचि और विश्वास को दर्शाता है।

कांग्रेस आज ज्ञापन देगी

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासप के निदेशानुसार प्रदेश की सभी जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आमजनता की समस्याओं एवं मांगों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने तथा सरकार को नींद से जगाने हेतु 1 अक्टूबर को जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम जन समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन दिया जाएगा।

जोन उपायुक्त ने प्रसंज्ञान लेकर आवास योजना की लाँटरी रोकी

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-14 के उपायुक्त दीपक सिंह खटाणा ने प्रसंज्ञान लेकर रियासत बिल्डर ग्रुप आवास योजना की लाँटरी पर रोक लगाई है। सूत्रों की मानें तो इस ग्रुप की अलग-अलग टाउनशिप में इंडब्ल्यूएस व एलआईजी केटेगिरी में 13 हजार आवेदन आ गए, जो निर्धारित प्लॉट्स की संख्या के कई गुना ज्यादा है। बड़ी संख्या में आवेदन आने की शिकायतें जब जेडीए पहुंची तो उपायुक्त ने इन पर प्रसंज्ञान लेते हुए लाँटरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब जेडीए खुद इन आवेदनों की छंटाई करेगा।

सूत्रों की मानें तो रियासत इफ्फा की जयपुर में कई टाउनशिप है। इनमें सभी में गर्बों और निर्धन वर्ग के आवास इंडब्ल्यूएस व एलआईजी की केटेगिरी रखनी पड़ती है। अलग अलग योजनाओं में इंडब्ल्यूएस व एलआईजी के लिए करीब 350 से अधिक प्लॉट आरक्षित किए हुए थे। जेडीए से अनुमति लेकर इन योजनाओं में यह आवेदन आरस्त में भरे गए थे। सितंबर इन योजनाओं की लाँटरी निकलनी थी। इन योजनाओं में भारी तलाव में आवेदन आए। आवेदनों की संख्या भी करीब 13 हजार थी।

जेडीए को शिकायत मिली थी कि इन योजनाओं में एक ही फोन से कई आवेदन भरे गए हैं। इनमें रियल स्टेट एजेंट भी शामिल है। गरीबों का एक वास्तविक लोगों तक पहुंचे इसके लिए जेडीए ने लाँटरी पर रोक लगा दी। अब

- रियासत बिल्डर ग्रुप की आवास योजनाओं में आवेदकों द्वारा एक ही मोबाइल नंबर से कई फार्म भरने की शिकायत पर कार्रवाई
- बताया जा रहा है कि, ग्रुप की अलग अलग टाउनशिप में ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. श्रेणी में 13 हजार आवेदन आए थे, जो कि निर्धारित प्लॉट्स की संख्या के कई गुना ज्यादा है।

जेडीए इन आवेदकों की जांच करा रहा है। इसके लिए रियासत ग्रुप से कहा गया है कि सभी योजनाओं के आवेदन जांच कर जेडीए के पास भिजवा दें।

सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार की "सबके लिए आवास" उपलब्ध कराने की मंशा के अनुसार राजस्थान अफोडेबल पॉलिसी 2010 जारी हुई थी। इस योजना में 10 हैक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल होने पर कुल योजना का पांच प्रतिशत अथवा कुल निर्मित यूनिट का 15 प्रतिशत जो भी अधिक हो, इंडब्ल्यूएस-एलआईजी के लिए आरक्षित किया जाना है।

इसके लिए आवेदन सबसे बाद में जेडीए से अनुमति लेकर मांगे जाते हैं। पहले तो सफल आवेदकों की लाँटरी निकालने का काम जेडीए के स्तर पर किया जाता था। मांग पत्र निकालने के बाद सफल आवेदक को रकम जमा करनी पड़ती थी। उसके बाद निजी खातेदार से एनओसी लेकर सफल आवेदक को भूखंड आवंटित कर दिया जाता था। इनकी रेट भी आरक्षित दर

की 50 से 80 फीसदी होती है। आरक्षित दर भी बिल्डर के भूखंड की दरों से लगभग चार गुना कम होती है।

सूत्रों की मानें तो निजी खातेदारी की आवास योजनाओं में इंडब्ल्यूएस, एलआईजी के आवेदन सभी के साथ नहीं मांगे जाते। पहले बिल्डर अपने भूखंड बेच लेता है और टाउनशिप को विकसित भी कर लेता है तब तक 3 साल निकल जाते हैं और रकमी में जमीनों की कीमत बढ़ जाती है।

उसके बाद जेडीए इंडब्ल्यूएस, एलआईजी के आवेदन मांगता है तो सस्ता भूखंड लेने के चक्कर में आवेदकों की बाढ़ आ जाती है। रियल स्टेट एजेंट की इसका लाभ उठाने से नहीं चूकते। वो भी भारी तलाव में आवेदन कर देते हैं जिससे वास्तविक गरीब व निर्धन वर्ग का हक मारा जाता है। बाद में ये एजेंट ही इन योजनाओं में आए भूखंडों को बाजार भाव से बेच देते हैं। बिल्डर खुद ही लाँटरी निकालता है जिसमें कई बार धांधली के भी आरोप लगे हैं।

तालकटोरे में मिला महिला का शव

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। माणक चौक थाना इलाके में स्थित तालकटोरे में सोमवार को एक महिला का शव पड़ा मिला। पानी की सतह पर महिला का शव देख वहां घूमने आए लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला और सर्वाई मानसिंह अस्पताल के मुद्दाम भिजवाया। पुलिस ने घटना स्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ की। लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई।

पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर 1 बजे के आसपास तालकटोरे में पानी की सतह पर एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम की मदद से शव को पानी से बाहर निकाल कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। लेकिन पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी।

मृतका की उम्र करीब 45 से 50 साल बताई जा रही है। दो -तीन पाला शव होने के कारण पानी में फूल गया और पानी से बाहर आ गया। पुलिस ने शव को सर्वाई मानसिंह अस्पताल के मुद्दाम भेज दिया कर दी है।

हनीट्रैप में फंसाकर 10 लाख रु. ऐंठने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के एक बड़े अधिकारी को हनीट्रैप में फंसाकर 10 लाख रुपय की वसूली करने के मामले में शिप्रापथ थाना पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक युवती समेत तीन अन्य आरोपियों को तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी वर्ष 2018 से अब तक पीड़ित अधिकारी से 10 लाख रुपय वसूल चुके थे। अब और रुपयों की मांग कर रहे थे। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों के पास पहुंच कर कहा कि "बचा लो... इतना परेशान हो गया हूँ कि आत्महत्या कर लूँ।"

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने 17 सितंबर को शिप्रापथ थाने में मामला दर्ज किया। डीसीपी (साउथ) सुरिंत आनंद ने बताया कि 13 दिनों में जांच पूरी कर करौली के दीपपुरा निवासी मस्तराम मोना उर्फ भूरा और उसके पिता शेर सिंह मोना को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शेर सिंह की बेटी नरेन्द्र कुमारी उर्फ नरसी, धर्मराज और वसूल किए गए 10 लाख रुपय के फोटो खींच ली।

इसके बाद उन्हें बदामान करने और बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपय वसूल लिए। इसके बाद, वर्ष 2021 में फिर से धमकी देकर 3 लाख रुपय और वसूल लिए। इस तरह लगातार धमकियां देकर कुल 10 लाख रुपय वसूलने के बाद भी आरोपी बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे थे।

सरकारी हॉस्पिटल में ओ.पी.डी. का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। सर्दी के सीजन की शुरुआत होने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी टाइमिंग में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत मंगलवार 1 अक्टूबर से हॉस्पिटल

में ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। जयपुर के एलएएस मेडिकल कॉलेज, आरयूपएस से अटेंच हॉस्पिटल समेत तमाम पीएचसी, सीएचसी, उप जिला हॉस्पिटल में आज

से ओपीडी के समय में बदलाव को आदेश जारी किए हैं। जेके लेन हॉस्पिटल जयपुर के अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मोना ने बताया कि ओपीडी का समय मंगलवार से सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।